

प्रेषक,

एल0 एम0 पन्त,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम,
देहरादून।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक : 06 अगस्त, 2010

विषय: 13वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु नगर निगम, देहरादून को प्रथम किश्त हेतु धनराशि का संकमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-417/XXVII(1)/2010 दिनांक 23 जुलाई, 2010 को निरस्त करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13वाँ वित्त आयोग, भारत सरकार की संस्तुतियों के क्रम में नगर निगम, देहरादून को वित्तीय वर्ष 2010-11 की प्रथम किश्त हेतु रु0 17871000.00 (रुपये एक करोड़ अठ्त्तर लाख इक्कहतर हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों के साथ संकमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संकमित की जा रही है :-

1. संकमित धनराशि का व्यय पेयजल, मल-जल व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्धन और स्ट्रीट लाइट पर किया जायेगा।
2. स्थानीय निकाय के लेखा परीक्षा तथा लेखा विवरण अद्यतन होनी चाहिये।
3. संकमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। संकमित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिये संकमित की गई है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा। इस धनराशि को वेतन/पेंशन आदि पर व्यय नहीं किया जायेगा।
4. अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र, मा0मेयर एवं मुख्य नगर अधिकारी के हस्ताक्षर से दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 तक प्राप्त हो जाने चाहिये।
5. शहरी विकास विभाग संकमित की जा रही धनराशि का नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित धनराशि वाउचर संख्या, दिनांक एवं व्यय की गई धनराशि का विवरण महालेखाकार, उत्तराखण्ड, प्रमुख सचिव, नगर विकास तथा वित्त आयोग निदेशालय को प्रेषित करना होगा।

6. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे।
7. अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये जाते हैं। समय से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने पर भारत सरकार द्वारा अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी। यदि उपयोगिता प्रमाण-पत्र के विलम्ब के कारण कोई धनराशि लैप्स होती है तो उसके लिये मुख्य नगर अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक-3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर-01 नगरीय स्थानीय निकाय-191-नगर निगम-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-0103-13वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,
6/8/2010
(एल0 एम0 पन्त)
सचिव, वित्त।

संख्या- 442 (1)/XXVII(1)/2010 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3. सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. निदेशक, नगरीय स्थानीय निकाय, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
8. निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
9. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

5/1

आज्ञा से,
6/8/2010
(एल0 एम0 पन्त)
सचिव, वित्त।